International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 6.340, Volume 03, No. 01, January - March, 2021, pp.305-311

# राजस्थान के औद्योगिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों की भूमिका

डॉ. हवा भंवर शेखावत*

**सार**

राजस्थान के औद्योगिक विकास में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कई संगठनों की भूमिका है । अगस्त 1986 में पुनर्गठित सरकार की उच्चाधिकार प्राप्त औद्योगिक सलाहकार परिषद् भी शमिल है, जिसके अध्यक्ष राज्य के उद्योग मंत्री है। परिषद् द्वारा समय–समय पर राज्य औद्योगिक विकास की प्रगति की समीक्षा की जाती है और इसके पश्चात् राज्य सरकार को औद्योगिक नीति एवं अन्य औद्योगिक कार्यक्रमों पर सलाह देने का कार्य किया जाता है तथा उद्योगों को समय–समय पर दी जाने वाली सुविधाओं, नियमें में सरकार द्वारा दी जाने वाली रियायतों का मूल्यांकन करके राज्य सरकार को प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। राज्य में वृहत एवं मध्यम उद्योगों के विकास में योगदान देने हेतू राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोग निगम लिमिटेड, राजस्थान वित्त निगम, सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो आदि हैं। ग्रामीण एवं लघु उद्योगों के विकास के लिए उद्योग निदे ाालय, खादी एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड, हथकरघा विकास निगम, राजस्थाल लघु उद्योग निगम आदि की स्थापना राजस्थान सरकार द्वारा की गई थी। इसके अतिरिक्त संघ सरकार द्वारा भी राज्य के औद्योगिक विकास में सहयोग प्रदान करने हेतू लघु उद्योग सेवा संस्थान, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, राजस्थान सलाहकार संगठन लिमिटेड आदि की स्थापना की गई थी जो राज्य सरकार के औद्योगिक विकास में अपनी–अपनी भूमिका निभा रहे हैं ।

***मुख्य शब्दः–*** *औद्योगिक विकास, औद्योगिक नीतियाँ, उद्योग, सार्वजनिक उपक्रम*

## प्रस्तावना

राजस्थान औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ प्रदेश है। राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 60 प्रतिशत भाग रेगिस्तान है जहां का आधारभूत ढांचा कमजोर होने के कारण औद्योगिक विकास की सम्भावनाएँ भी कम है। इंदिरा गाँधी नेहरू के कारण सिंचाई की सुविधाएँ बढ़ी है लेकिन औद्योगिक विकास की दौड़ में आज भी पिछड़ा हुआ है। राजस्थान के शेष 40 प्रतिशत भौगोलिक भाग में भी औद्योगिक सम्भावनाएँ कमजोर आधारभूत ढांचे के कारण पिछड़ी हुई है। भारत एवं राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक विकास के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति से आज तक अनवरत प्रयास किये गये लेकिन इन सबके बावजूद भी राजस्थान औद्योगिक दृष्टि से बिहार, उड़ीसा जैसे बीमारू राज्यों की पंक्ति में खड़ा है। राजस्थान में हीरे एवं जवाहरात, रेडीमेड वस्त्र, हस्तशिल्प एवं हैण्डीक्राफ्ट तथा मार्बल जैसे उद्योगों का विकास हुआ। खनिज उत्पाद पर आधारति उद्योग स्थापित हुए इसके बावजूद भी राजस्थान का पर्याप्त औद्योगिक विकास नहीं हुआ। भारत एवं राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए उनके वित्तीय एवं औद्योगिक क्षेत्र की सार्वजनिक इकाइयों की स्थापना की जो निम्नलिखित हैं :–

[6] एसिस्टेन्ट प्रोफेसर (व्यवसायिक प्रबन्ध), सोनादेवी सेठिया गर्ल्स पी.जी. कॉलेज, सुजानगढ़, राजस्थान।

- **भारत सरकार द्वारा संचालित सार्वजनिक क्षेत्र की वित्तीय इकाइयाँ**

भारतीय सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं द्वारा राज्य के औद्योगिक विकास के लिए अल्पकालीन, मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है । भारत सरकार द्वारा संचालित सार्वजनिक क्षेत्र की निम्नलिखित इकाइयों ने राज्य के औद्योगिक विकास में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से योगदान दिया है ।

- **भारतीय औद्योगिक वित्त निगम :–** भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना 1 जुलाई 1948 को संसद के विशेष अधिनियम के अन्तर्गत भारत की प्रथम विकास वित्त संस्था के रूप में हुई थी। 21 मई 1993 को भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड का गठन एक कम्पनी के रूप में किया गया। निगम की स्थापना का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक एवं निजी तथा सहकारी संस्थाओं को मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन वित्तीय सहायता प्रदान करना है जो उत्पादन, खनन, विद्युत उत्पादन एवं वितरण, होटल आदि व्यवसाय में लग हुई हो । निगम अपनी बढ़ती गैर–निष्पादित सम्पत्तियों के कारण निरन्तर घाटे में चल रहा है । निगम द्वारा वितरित कुल सहायता राशि में से राजस्थान को 4.3 प्रतिशत वितरित की गई जो अपेक्षाकृत कम है ।
- **भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम :–** अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निमाण एवं विकास बैंक तथा अमेरिकी सरकार के प्रतिनिधियों ने 1954 में भारत भ्रमण तथा अध्ययन करते समय दिये गये सुझाव को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने 5 जनवरी 1955 को भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम की स्थापना भारत सरकार, अमेरिकी सरकार, इंग्लैण्ड तथा भारतीय विनियोक्ताओं के सहयोग से की गई थी। निगम की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य निजी क्षेत्र में स्थापित औद्योगिक इकाइयों के विकास के लिए दीर्घकालीन वित्तीय सहायता प्रदान करना है। भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करने के साथ–साथ नई कम्पनियों के अंशो एवं ऋणपत्रों का अभिगोपन करना, निजी कम्पनियों के ऋपत्रों एवं बोन्डों में विनियोग करना आदि कार्य किये जाते हैं। निगम के निजी प्रयासों से भारतीय विनियोग केन्द्र की स्थापना हो सकी है जो निजी विदेशी पूँजी को भारत में विनियोग करने को प्रोत्साहित करता है ।
- **भारतीय औद्योगिक विकास बैंक :–** भारत में औद्योगिक वित्त प्रदान करने हेतू भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गई। इस बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1964 को की गई थी। प्रारम्भ में यह बैंक देश के केन्द्रीय बैंक से सम्बद्ध था लेकिन 16 फरवरी 1976 को बैंक का पुर्नगठन करके इो केन्द्रीय बैंक से पृथक कर दिया गया। इस बैंक के पुर्नगठन का उद्देश्य अखिल भारतीय एवं राज्य स्तर पर वित्तीय संस्थाओं एवं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको के मध्य समन्वय स्थापित करना था। इस बैंक की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य नई परियोजनाओं के लिए वित्त एवं वित्तीय सेवाएँ उपलब्ध करवाना है। इसे साथ–साथ यह बैंक विद्यमान औद्योगिक इकाइयों के विस्तार, नवीनीकरण, आधुनिकीकरण, तकनीकी उन्यन आदि के लिए वित्त प्रदान करता है ।
- **भारतीय औद्योगिक विनियोग बैंक :–** विनियोग बैंक की स्थापना 1971 में भारतीय औद्योगिक पुनर्निमाण बैंक के नाम से की गई थी तथा 1997 में असका नाम बदलकर भारतीय औद्योगिक विनियोग बैंक कर दिया गया । इसकी स्थापना का प्रमुख उद्देश्य बीमार औद्योगिक इकाइयों को पुनः जीवित करने तथा अनार्थिक उपक्रमों में लाभ क्षमता उत्पन्न करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। बैंक उद्यामियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के साथ–साथ तकनीकी तथा प्रबंधकीय सहायता भी उपलब्ध कराता है। बैंक द्वारा औद्योगिक इकाइयों के विस्तार, सुधार विविधकरण, पुर्नसंगठन, आधुनिकीकरण आदि कार्यो द्वारा उनका पुनः निर्माण किया जाता है ।
- **राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक :–** इस बैंक की स्थापना जुलाई 1982 में की गई थी । इस बैंक का प्रमुख उद्देश्य कृषि एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कार्यरत अन्य वित्तीय संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है एवं उनका मार्गदर्शन करना है। यह बैंक कृषि, हस्तशिल्प, कुटीर

एवं ग्रामीण उद्योगों को ऋण उपलब्ध करवाने हेतु नीतियों एवं योजनाएँ बनाता है तथा उन्हें व्यापारिक सहकारी एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से क्रियान्वित करवाता है। नाबार्ड उपेक्षित क्षेत्रों को प्राथमिकता में रखकर ऋण प्रदान करने के निर्देश बैंको को जारी करता है। यह कार्य नाबार्ड की स्थापना से पूर्व रिजर्व बैंक द्वारा किये जाते थे ।

- **भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक लिमिटेड :–** भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक लिमिटेड की स्थापना 1989 में संसद के अधिनियम द्वारा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्था के रूप में की गई थी। सिडबी ने 2 अप्रैल 1990 से अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया था। इसकी स्थापना का प्रमुख उद्देश्य लघु एवं कुटीर उद्योगों के संवर्धन वित्त पोषण और विकास का कार्य करती है तथा इसके साथ–साथ इसी काम में लगी अन्य संस्थाओं के कार्यो में समन्वय करने का दायित्व भी उठाती है ।
- **राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड :–** राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड की स्थापना 1955 में एक सरकारी कम्पनी के रूप में की गई थी। इसकी स्थापना का प्रमुख उद्देश्य उद्यमियों को कच्चे माल, पुर्जे एवं उपकरणों की आपूर्ति करना है। यह निगम प्रोटोटाइप मशीनों का विकास करता है तथा लघु क्षेत्र के कामगारों को प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराना है। निगम लघु इकाइयों को उनके माल के विपणन तथा निर्यात में सहायता प्रदान करता है ।

- **भारत सरकार द्वारा संचालित सार्वजनिक क्षेत्र की औद्योगिक इकाईयाँ**

भारत सरकार द्वारा राज्य के औद्योगिक विकास को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम स्थापित किये गये :

- **हिंदुस्तान जिंक लि. उदयपुर :–** उदयपुर के पास स्थित जावर खानों के जस्ता एवं सीसे के भण्डारों के विदोहन हेतु 1965 में देबारी में जस्ता गलाने का कारखाना खोला गया जिसकी क्षमता 10 हजार टन वार्षिक से बढ़ाकर अब 36 हजार टन कर दी गई है। यहाँ पर खाद भी बनाया जाता है। इसी के अन्तर्गत एक और कारखाना चितौड़ में 617 करोड़ रूपये की लागत से बनाया गया है। जिसकी एक इकाई आंगूजा में भी है ।
- **हिन्दुस्तान कॉपर लि., खेतड़ी :–** खेतड़ी की तांबा खानों से प्राप्त तांबे को गलाने हेतु 1967 में यह कारखाना खोला गया था। इसकी क्षमता 36 हजार टन से बढ़ाकर 45 हजार टन करने का लक्ष्य है।
- **हिन्दुस्तान मशीन टूल्स निगम, अजमेर :–** 1967 मेंचेकोरलोवाकिया के तकनीकी सहयोग से स्थापित किया गया है, जहाँ मशीनी उपकरण व घड़ियों के पुर्जे बनाने की व्यवस्था है ।
- **इन्स्ट्रूमेंटेशन लि., कोटा :–** देश में थर्मल पावर, स्टील एवं रासायनिक उद्योगों के काम में आने वाले औद्योगिक संयंत्र बनाता है और निर्यात भी करता है ।
- **सांभर साल्ट्स लि., सांभर :–** कई तरह के नमक तैयार करने के लिए 1964 में यह हिन्दुस्तान साल्ट्स की सहायता संस्था के रूप में प्रारम्भ की गई है।

निकट भविष्य में भारत सरकार, राजस्थान में झामरकोटड़ा (उदयपुर) के रॉक– फोरफेट तथा सलादीपुरा (सीकर) के पॉयराइट भण्डारी के विदाहन हेतु उर्वरक संयंत्र स्थापित करेगी । जिनमें लगभग 250 करोड़ रूपये का विनियोग होने की संभावना है। जयपुर में मोडर्न बेकरीज इण्डिया लि. भी स्थापित की गई है। जस्ता गलाने का एक संयंत्र चन्देरिया (चितौड़) में स्थापित किया गया है ।

- **राजस्थान सरकार द्वारा संचालित सार्वजनिक क्षेत्र की वित्तीय इकाईयाँ**

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही भारत का औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ राज्य रहा है। राजस्थान में अनेक औद्योगिक घराने होने के बाद भी प्रदेश का औद्योगिक विकास नहीं हो पाया है। बिड़ला, डालमिया,

सिंघानिया, पोटदार, बजाज आदि अनेक विश्व प्रसिद्ध औद्योगिक घराने राजस्थान में जन्म लेकर आगे बढ़े है लेकिन इसके बावजूद भी राजस्थान औद्योगिक दृष्टि से बीमारू राज्यों की पंक्ति में खड़ा है। राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के औद्योगिक विकास के लिए निम्नलिखित सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की स्थापना की गई :–

- **राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास व विनियोग निगम लि. (रीको)**

इस निगम की स्थापना 1969 में हो चुकी थी, लेकिन नवम्बर, 1979 में राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम के अलग से स्थापित होने के बाद रीको के कार्य औद्योगिक विकास के क्षेत्र तक सीमित कर दिया गया। इसे कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत एक सार्वजनिक सीमित दायित्व वाली कम्पनी के रूप में स्थापित किया गया था। निगम के मुख्य उद्देश्य राज्य में औद्योगिक संरचना विकास व औद्योगिक क्षेत्र विकसित करना, मध्यम व वृहद् उद्योगों को अवधि ऋण उपलब्ध कराना तथा उन्हें तकनीकी सलाह, मर्चेन्ट बैकिंग गतिविधियों व इक्विटी सहभागिता द्वारा औद्योगीकरण को प्रोत्सहित करना है।

निगम के मुख्य कार्य इस प्रकार है :

- वृहद, मध्यम व लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना ।
- आधारभूत सुविधाएँ प्रदान कर लघु, मध्यम एवं वृहद् श्रेणी के उद्योग स्थापित करने हेतु औद्योगिक क्षेत्र विकसित करना ।
- औद्योगिक व्यापार एवं विनियोजन संवर्द्धन का कार्य।
- मर्चेन्ट बैंकर के रूप में कार्य करना ।
- औद्योगिक परियोजनाओं के संबंध में परियोजना प्रतिवेदन व रूपरेखा तैयार करना तथा तकनीकी सलाहकारी सेवाएँ प्रदान करना ।
- सरकार की ओर से उद्योगों के विकास हेतु वि ोष वित्तीय रियायतें व प्रोत्साहन उपल्ब्ध कराना ।

रीको भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) से पुनर्वित्त के रूप में सहायता प्राप्त करता है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने रीको के कार्य की प्रगति को देखकर इसे पुनर्वित्त की स्कीम में रियायतें दी है। और सितम्बर 1976 में रीको को वित्तीय संस्था के रूप में मान्यता प्रदान की, जिसके बाद इसकी विनियोग संबंधी क्रियाओं में काफी वृद्धि हुई है। रीको पिछड़े क्षेत्रों एवं जनजाति क्षेत्रों में औद्योगिक प्रोजक्ट लगाकर उनके विकास के लिये प्रयत्नशील रहा है ।

रीको ने संयुक्त क्षेत्र में औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहन दिया है। संयुक्त क्षेत्र के प्रोजेक्टों में अंधिकांश इकाइयाँ कार्पेट यार्न व सिन्थेटिक यार्न बनाती है। रीको ने स्वयं के सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र व सहायता क्षेत्र सभी का विकास करने का प्रयास किया है। कुछ प्रोजक्टों में विदेशी टेक्नोलॉजी का भी उपयोग किया गया है। रीको इलेक्ट्रानिक परियोजनाओं के विकास पर भी समुचित ध्यान दे रहा है। इसकी इलेक्ट्रानिक्स की इकाइयाँ लघु मध्यम व बड़ी सभी आकार की है। रीको नये प्रोजेक्ट के साथ–साथ अन्य बड़े प्रोजक्टों के साथ टाइ–अप, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के सहयोग से विनियोग को आकर्षित करता रहा है। रीको ने प्राइवेट इन्जीनियरिंग, मेडिकल कालेजों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, सिनेमाघरों टेक्सटाइल और होटल उद्योग आदि की स्थापना के लिये वित्तीय सहायता प्रदान की है। जिसमें इक्विटी में योगदान, दीर्घकालीन ऋण, ब्याजमुक्त कर्ज तथा विनियोग सबिसडी प्रदान करना है ।

रीको द्वारा देश विदेशो में बसे प्रवासी भारतीयों, राज्य के बाहर काम करने वाले प्रवासी राजस्थानियों व अन्य लोगों को राजस्थान में विनियोग करने हेतु आकर्षित करने के लिए विभिन्न स्थानों पर औद्योगिक अभियान आयोजित किये गये हैं। रीको भूमि प्राप्त करने व विकसित करने के कार्य में काफी सक्रिय रहा है, किन्तु अधिकांश क्षेत्रों में जल, परिवहन व संचार की सुविधाओं में कमी के कारण उद्यमकर्ताओं को कठिनाई का सामना करना पड़ता है, इस संबंध में सुधार की नितान्त आवश्यकता है ।

दिल्ली के समीप होने के कारण राजधानी प्रदेश के अलवर जिले में नये औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने पर बल दिया जा रहा है। भिवाड़ी का फ्लेगशिप क्षेत्र खुशखेड़ा विस्तार मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये जा रहे है। आबू रोड, बीकानेर, भीलवाड़ा, धौलपुर, पलसाना, परबतसर, करणी आदि 8 विकास केन्द्रों की स्थापना की है। वही भारत सरकार की समन्वित आधार ढांचा विकास स्कीम के तहत लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने हेतु सांगरिया (जोधपुर), गोगेलाव (नागौर), निवाई (टोंक), कल्लडवास (उदयपुर), फालना (पाली), हिन्डोन सिटी (करौली), बयाना (भरतपुर), धोहिन्दा (राजसमन्द) तथा बांरा 9 स्थानों पर लघु विकास केन्द्र (आई.आई.डी) स्थापित किये गये है । विशेष उद्देश्यों की पुर्ति हेतु (जेम्स, ज्यूलरी, चमड़ा, दस्तकारी आदि) औद्योगिक पार्क विकसित किये जा रहे है। औद्योगिक सेवा व व्यापार संबंधी क्रियाओं के लिये सीमा शुल्क मुक्त, विदेशी निवेश से युक्त दो स्पेशल जोन (सीतापुरा चरण I, II जयपुर व बोरानाडा जोधपुर में) विकसित किये गये है। अजमेर रोड पर महापुरा के पास औद्योगिक टाउनशिप व रिहायशी बस्तियों का निर्माण करने हेतु एक सेज विकसित करने की योजना बनायी गई ।

रीको ने स्टोन्स विकास के लिये एक केन्द्र सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र जयपुर में स्थापित किया है। 1998 में सीडीओएस को एक समिति के रूप में पंजीकृत कियागया, इसका कार्य संचालन 37 सदस्यों के एक संचालक मण्डल द्वारा किया जायेगा। इससे स्टोन संबंधी उद्योगों को विभिन्न सुविधायें मिलेगी। रीको ने 'उद्योगश्री' नाम की एक स्कीम भी चालू की है, जिसका उद्दे य उद्यमकर्ता की योग्यता रखने वाले पे ोवर लोगों को आकर्षित करना है। इस प्रकार रीको राजस्थान के औद्योगिक विकास में काफी सक्रिय भूमिका अदा कर रहा है।

- **राजस्थान वित्त निगम :**

लघु व मध्यम पैमाने के उद्योगों को वित्तीय सहायता देने के लिए 1955 में राजस्थान वित्त निगम स्थापित किया गया था। यह एक वैधानिक निगम है, जिसे राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत स्थापित किया गया है। इस निगम के मुख्य उद्देश्य राज्य की अतिलघु, लघु व मध्यम पैमाने की औद्योगिक इकाइयों को मध्यम व दीर्घकालीन वित्तीय सहायता देना, राज्य के तीव्र औद्योगिकरण में सहयोग देना तथा औद्योगिक गति को नया आयाम देना, स्थापित उद्योगों के विस्तारीकरण तथा नवीनीकरण हेतू ऋण उपलब्ध कराना एवं राज्य सरकार के अधिकर्त्ता की भूमिका के रूप में कार्य करना है।

निगम के प्रमुख कार्य इस प्रकार है :–

- निगम द्वारा औद्योगिक इकाइयों को 20 करोड़ तक के ऋण उपलब्ध कराये जाते है ।
- औद्योगिक इकाइयों को ऋण स्वीकृत करने हेतु केन्द्र सरकार, राज्य सरकार IDBI व IFCI के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना ।
- ऋणों की गारण्टी देना ।
- अंशों व ऋणपत्रों का अभिगोपन करना ।
- उपकरण पुनर्वित्त करना ।

राजस्थान वित्त निगम द्वारा उद्योगों की स्थापना हेतू ऋण लेने वाले अच्छे उद्यमियों की प्रोत्साहित करने हेतू 'फ्लैक्सी ऋण योजना' प्रारम्भ की गई। वर्तमान ऋण प्राप्त MSME की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 'टॉप–अप ऋण योजना', 'महिला उद्यमनिधि योजना' महिला उद्यमियों को, 'सेमफक्स योजना 'भूतपूर्व सैनिको को स्वरोजगार प्रदान करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके साथ ही शिल्पकारी योजना, सिल्वर कार्ड योजना, गोल्ड कार्ड स्कीम, प्लेटीनम कार्ड स्कीम, टेक्नोक्रट स्कीम चलायी जा रही है ।

- **सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो**

राजस्थान राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो की स्थापना की गई है, जिसमें वित्त सचिव व उद्योग सचिव भी सदस्य है। इसमें राजकीय उपक्रमों में दो मुख्य अधिकारी व दो अन्य

विशेषज्ञ भी सदस्य के रूप में लिए जाते हैं। ब्यूरो के कार्यो में प्रकार – सभी राजकीय सार्वजनिक उपक्रमों के कार्यो की समीक्षा करना व इनका मूल्यांकन करना, इनके प्रबंध, टेक्नोलोजी आदि के सुधार के उपाय सुझाना, विभिन्न उपक्रमों में कर्मचारी संबंधी नीतियों, कल्याण कार्यो, मजदूरी–ढांचे आदि में समरूपता लाना, कर्मचारियों के प्रशिक्षण स्टाफ भवन–निर्माण की स्कीमों आदि की सुविधाओं की व्यवस्था करना तथा, उपक्रमों के बारें में सूचना एकत्र करना व उसे प्रसारित करना ।

- **उद्योग निदेशालय**

इसका मुख्य उद्देश्य लघु टाइनी, ग्रामीण व दस्तकारी क्षेत्र के विकास में मदद करना है ताकि राज्य का तेजी से औद्योगीकरण हो सके। इसके लिए यह जिला उद्योग केन्द्रों के लिए वार्शिक कार्यकारी योजनाएँ बनाता है, लघु व शिल्पकारों की इकाइयों का पंजीकरण करता है, रूथानीय साधनों का उपयोग करके रोजगार संवर्द्धन व विकास में प्रादेशिक संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। यह औद्योगिक सर्वेक्षण करता है तथा प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने में सहायता देता है। यह औद्योगिक अभियान में योगदान देता है। इसके कार्य विविध प्रकार के होते है। यह वित्तीय सहायता, विपणन, निर्यात–प्रोत्याहन, औद्योगिक विकास, नमक उद्योग, रूग्ण व बंद इकाइयों आदि के संबंध में आवश्यक योगदान देता है ।

- **जिला उद्योग केन्द्र**

यह जिला स्तर पर एक केन्द्र चलित कार्यक्रम है जो कुटीर, ग्रामीण लघु व टाइनी उद्योगों से संबंधित सेवाएँ प्रदान करता है। इससे ग्रामीण व छोटे कस्बों में उद्योगों का प्रोत्साहन मिलता है तथा बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर खुलते हैं। वर्तमान में राज्य में 33 जिला उद्योग केन्द्र व 8 उपकेन्द्र कार्यरत है। ये साधनों की उपलब्धि की जाँच करते है, साख व ग्रामीण उद्योग बोर्ड, हथकरघा विकास निगम, राजसिकों आदि के बीच कड़ी स्थापित करने का कार्य करते हैं। इनके अलावा राजस्थान खादी व ग्रामीा उद्योग बोर्ड, हथकरघा विकास निगम आदि संस्थाऐं भी अपने–अपने क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों का विकास करने में कार्यरत है ।

- **राजस्थान लघु उद्योग निगम**

राजस्थान में लघु, कुटीर, दस्तकारी, टाइनी उद्योगों की संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से राजसिको की स्थापना जून, 1961 में की गई थी। लघु उद्योगों को कच्चा माल एवं वित्तीय सहायता राजसिको द्वारा उपलब्ध कराई जाती है तथा इन उद्योगों कातैयार माल के विपणन की व्यवस्था भी राजसिको स्वयं ही करता है। राजसिको लघु एवं कुटीर उद्योगों के उत्पादों का निर्यात भी करता है। भारत वर्ष में राजस्थली के नाम से राजसिको के विक्रय केन्द्र भी स्थापित हैं और प्रतियोगिता में अग्रणी स्थान रखते हैं ।

- **राजस्थान सरकार द्वारा संचालित सार्वजनिक क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयाँ**

राजस्थान सरकार ने भी औद्योगीकरण हेतु स्वयं साहसी के रूप में उपक्रम स्थापित किये हैं। जो निम्नलिखित है :–

- **हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री, धौलपुर :–** यह प्रयोगशालाओं में काम आने वाला कांच का सामान बनाती है ।
- **गंगानगर शुगर मिल्स :–** श्रीगंगानगर के अन्तर्गत चीनी उत्पादन मिला तथा पांच डिस्टलरीज हैं। गन्ने व चुकन्दर से चीनी बनाई जाती है ।
- **राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स :–** डीडवाना के अन्तर्गत सोडियम सल्फेट संयंत्र लगाया गया है। इसके अन्तर्गत ही कास्टिक सोडा, ऐश, सोडियम सल्फाइड आदि रयायनों के बनाने की भी व्यवस्था की जा रही है ।
- **साल्ट वर्क्स डीडवाना एवं पंचभद्रा :–** उपक्रमों में खाने का तथा औद्योगिक नमक तैयार किया जाता है ।

- **टोंक में चमड़ा बनाने का कारखाना :–** राजस्थान स्टेट टेनीरीज लि. के अन्तर्गत स्थापित किया गया है ।
- **स्टेट वूलन मिल्स, बीकानेर :–** गलीचे, कम्बल, बनियान तथा बुनाई, ऊन का धागा बनाने के लिये 1968 में स्थापित की गई । उत्पादन क्षमता में वृद्धि हेतू 1200 तकुओं की और वृद्धि की जानी है।
- **वास्टेड वूलन मिल्सए लाडनूं एवं चुरू :–** इस वूलन मिल में ऊन कपड़ों का निर्माण किया जाता है। इस क्षेत्र में अनेक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाता है ।

स्वतंत्रता प्राप्ति से आज तक संघ एवं राज्य सरकार के द्वारा औद्योगिक विकास के प्रभावी प्रयास किये गये हैं । संघ सरकार द्वारा औद्योगिक विकास हेतु वित्तीय एवं औद्योगिक क्षेत्र में अनेक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना की । जिनमें प्रमुख रूप से भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक लि., राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि., हिन्दुस्तान जिंक लि., हिन्दुस्तान कॉपर लि., हिन्दुस्तान मशीन टूल्स निगम आदि हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की वित्तीय इकाइयाँ आज भी राज्य के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं लेकिन औद्योगिक इकाइयाँ धीरे–धीरे घाटे में चल रही हैं। वे इकाइयाँ भी स्थापना से लेकर 1990 से पूर्व तक औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रही थी लेकिन आज इनमें कर्मचारियों की संख्या, लाभदायकता एवं उत्पादन सभी में दिन प्रतिदिन कमी हो रही है और इन इकाइयों को निजी क्षेत्र को सौंपने की तैयारी कर रही है ।

राजस्थान सरकार द्वारा रीको, राजस्थान वित्त निगम, जिल उद्योग केन्द्र, राजसिकों एवं अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करके राज्य के औद्योगिक विकास को बढ़ाने में योगदान दे रही है। औद्योगिक इकाइयाँ लगभग घाटे में चल रही है । रीको एवं राजस्थान वित्त निगम राज्य के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं लेकिन राजसिकों अपनी प्रभावी भूमिका निभाने में असमर्थ रहा है। अतः निगम के द्वारा संचालित नीतियों में आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है ताकि राजस्थान अपने औद्योगिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतू अग्रसर हो सकें ।

**संदर्भ ग्रन्थ सूची**


~ आर्थिक समीक्षा, भारत सरकार , 2012, नई दिल्ली ।

~ आर्थिक समीक्षा, राजस्थान सरकार 2012, जयपुर ।

~ पार्षद सीमा नियम, रीको, राजस्थान सरकार, 2008 जयपुर ।

~ वार्षिक प्रतिवेदन, रीको राजस्थान सरकार, 2009 जयपुर ।

~ लक्ष्मीनारायण नाथूरामका, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, कॉलेज बुक हाउस, 2012 जयपुर

~ कान्ति जैन, महावीर जैन राजस्थान का भूगोल व अर्थव्यवस्था, मनु प्रकाशन, 2018, जयपुर ।

~ प्रकाश नारायण नाटाणी, अपना राजस्थान, पिंकसिटी पब्लिशर्स, 2009 जयपुर ।

~ वार्षिक प्रतिवेदन, राजस्थान वित्त निगम, 2010 जयपुर ।.


❖◆❖